राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 2745/2024

राम कुमार पुत्र श्री जगदीश, उम्र लगभग 36 वर्ष, वर्तमान में गोगामेडी मंदिर के पास निवास, मुकलावातेह, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, राज.

----अपीलार्थी

बनाम

1. मनीष कुमार पुत्र सेठ प्रकाश, निवासी मुकलावा तह., रायसिंहनगर, अनूपगढ़, राज.
2. राजस्थान राज्य पीपी के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री नरपेन शंकर आचार्य

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुक्तियार खान, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

08/07/2024

1. विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसिंहनगर, राजस्थान द्वारा पारित दिनांक 16.11.2023 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता/अभियुक्त द्वारा धारा 389 सीआरपीसी के तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपील में दायर आवेदन को अंतरिम मुआवजे के रूप में 20% जमा करने की शर्त पर अनुमति दी गई थी।

2. आक्षेपित आदेश मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, सजा का निलंबन केवल तभी हो सकता है जब जुर्माने की राशि का कम से कम 20% शिकायतकर्ता को भुगतान किया जाए।

3. इसके अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने जुर्माना राशि का 20% अंतरिम भुगतान करने का निर्देश देते समय गंभीर गलती की है, क्योंकि उसे लगता था कि एन.आई. अधिनियम की धारा 148 के तहत निहित प्रावधान

निरपेक्ष प्रकृति का है और इसके अनुपालन के बिना, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस संबंध में, जम्बू भंडारी बनाम एम.पी. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और अन्य: (2023) 10 एससीसी 446 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है। इसके प्रासंगिक विवरण नीचे दिए गए हैं:

> "6. इस न्यायालय का मानना है कि एन.आई. अधिनियम की धारा 148 की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। इसलिए, सामान्यतः, अपीलीय न्यायालय धारा 148 में प्रावधानित जमा की शर्त लगाने में न्यायोचित होगा। हालांकि, ऐसे मामले में जहां अपीलीय न्यायालय संतुष्ट है कि 20% जमा की शर्त अनुचित होगी या ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के अपील के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, विशेष रूप से दर्ज किए गए कारणों के लिए अपवाद बनाया जा सकता है।
>
> 7. इसलिए, जब अपीलीय न्यायालय एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्त की सीआरपीसी की धारा 389 के तहत प्रार्थना पर विचार करता है। अधिनियम के अनुसार, अपीलीय न्यायालय के लिए यह विचार करना हमेशा खुला है कि क्या यह एक अपवादात्मक मामला है, जिसके लिए जुर्माना/मुआवजा राशि का 20% जमा करने की शर्त लगाए बिना सजा को निलंबित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है, यदि अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह एक अपवादात्मक मामला है, तो उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।
>
> 8. मूल शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का यह तर्क है कि न तो सत्र न्यायालय के समक्ष और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा यह दलील दी गई थी कि इन मामलों में अपवाद बनाया जा सकता है और न्यूनतम 20% राशि जमा करने की आवश्यकता को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अपीलकर्ताओं द्वारा ऐसी प्रार्थना नहीं की गई थी, तो न्यायालयों के पास उक्त दलील पर विचार करने का कोई कारण नहीं था।

9. हम उपरोक्त दलील से असहमत हैं। जब कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत सजा के निलंबन के लिए आवेदन करता है, तो वह आम तौर पर बिना किसी शर्त के सजा के निलंबन से राहत के लिए आवेदन करता है। इसलिए, जब अपीलकर्ताओं द्वारा एक व्यापक आदेश मांगा जाता है, तो अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि मामला अपवाद में आता है या नहीं।

10. इन मामलों में, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने गलत आधार पर आगे बढ़े हैं कि न्यूनतम 20% राशि जमा करना एक पूर्ण नियम है जो किसी भी अपवाद को समायोजित नहीं करता है।

11. इस स्तर पर अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने कहा है कि अपीलकर्ताओं ने मुआवजे की राशि का 20% जमा कर दिया है। हालांकि, यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा जांचा जाना है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता बहुत गरीब व्यक्ति है और उसका पूरा परिवार गरीबी में जी रहा है। आर्थिक तंगी के कारण वह इतनी बड़ी राशि यानी 2,00,000/- रुपये कुल राशि का 20% (10,00,000/- रुपये मुआवजा के रूप में) जमा करने की स्थिति में नहीं है।

5. इस आधार पर उसे हिरासत में लिए जाने के लिए अनिवार्य रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। इसलिए वह अपील के लंबित रहने के दौरान अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता दांव पर है।

6. जबकि, दूसरी ओर, वह इस बात को लेकर आशान्वित है कि उसके पास अपील में एक अच्छा मामला है। वह इसमें सफल होगा, लेकिन भुगतान करने में असमर्थता के कारण वह आगे की कार्यवाही में अपना बचाव करने में सक्षम नहीं है जब तक कि वह यहां दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करता।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलें सुनने के बाद मैं उनके द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत हूँ।

8. इस आधार पर, आक्षेपित आदेश और केस फाइल को देखने के बाद, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, उसे आक्षेपित आदेश के अनुसार राशि का 20% जमा करने का निर्देश देने से उसकी अपील को जोखिम

में डाला जा सकता है, क्योंकि जमा की शर्तों का पालन न करने के कारण उसे खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि वह वित्तीय संकट में है और उसे लंबित अपील में अपना बचाव करने में सक्षम बनाने के लिए न्याय के व्यापक हित में छूट दी जानी चाहिए।

9. परिणामस्वरूप, जंबू भंडारी (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। विद्वान सत्र न्यायाधीश अग्रिम जमा पर जोर दिए बिना अपील की सुनवाई करेंगे तथा कानून के अनुसार उसका निपटारा करेंगे।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।